किसान क्रांति यात्रा

किसानों ने जब निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर दिल्ली की सीमा में जबरन घुसने का प्रयास किया तो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान सख्ती पर उतर आए। अवरोधक तोड़ रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की और आखिर में लाठियां भी बरसानी पड़ीं। सुबह से शाम तक जो कुछ हुआ, आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं हमारे फोटोग्राफर इमरान और अमित।

किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी किसान नहीं हटे। किसानों ने वॉटर कैनन व आंसू गैस के बीच ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया।

जब आमने-सामने हुए किसान और जवान

किसानों के बुलंद हौसलों के बीच उन्हें दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग की, बाद में ट्रैक्टर और ट्रॉली के पहिये पंक्चर कर दिए।

यूपी गेट पर संघर्ष के दौरान ऐसे मौके भी आए जब किसानों ने भी लाठियों के विरोध में लाठियां उठा लीं।

भगदड़ में घायल हुए किसान

तैयार किसान, मुस्तैद जवान

किसानों का संख्या बल देखे हुए पुलिस पहले से तैयार थी। किसान भी आगे बढ़ने की ठान कर आए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग के साथ सड़क के दोनों तरफ से करीब 500 मीटर तक वाहनों को खड़ा कर दिया गया था। इससे बड़े वाहनों को लेकर निकलना संभव नहीं था। अगर किसान बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसते भी तो वह वाहन लेकर अंदर नहीं जा पाते। उनकी ये योजना काम भी कर गई। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ तो ली मगर वो शहर के भीतर नहीं घुस पाए। दिल्ली पुलिस ने वाहनों से सड़क ब्लॉक कर रोकने की योजना भी तैयार कर रखी थी। यूपी बॉर्डर के अलावा पुलिस पुलिस की तरफ से अंदर की सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई थी। जहां भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिसकर्मियों की तरफ से बड़े वाहनों पर नजर रखी जा रही थी। अगर कोई किसान दिल्ली में प्रवेश भी कर ले रहा था, अंदर की सड़कों पर तैनात पुलिस उन्हें वापस भेज दे रही थी।

यूपी गेट पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों की मानी गईं मांगों को पढ़कर सुनाया।

यूपी गेट पर मंगलवार को किसानों ने जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने पानी की बौछार से उन्हें तितर-बितर किया। इसमें कुछ किसान घायल हो गए।

जमावड़े से शहर में एक अलग गांव बस गया

ट्रांस हिंडन | **नितिन कुमार**

लिंक रोड पर सोमवार शाम साहिबाबाद सब्जी मंडी के आसपास बने आलीशान फार्म हाउसों में किसानों के कदम रखते ही गांव जैसा माहौल बन गया। जैसे ही किसानों ने रात्रि विश्राम लिंक रोड पर करने की घोषणा की वैसे ही पूरे लिंक रोड पर चार किलोमीटर के दायरे में किसानों ने अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए।

इसके बाद फार्म हाउस, सड़क और पार्कों में किसानों ने चादरें बिछा दीं। यात्रा में थके कुछ किसान सो गए, वहीं कुछ देर रात तक ताश खेलते और हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। शाम ढलने के साथ-साथ जहां यात्रा की थकान किसानों पर हावी हो रही थी, वहीं उन्हें भूख भी सताने लगी थी। आनन-फानन में गैस सिलेंडर और चूल्हा निकालकर सड़क पर ही रसोई बना दी गई।

हंसी-ठिठोली और यात्रा की आगे की रणनीति के बीच नमक-मिर्च से बने सादे भोजन ने यात्रा की थकान मिटाते हुए आगे बढ़ने के लिए स्फूर्ति भर दी। इस बीच इसका ख्याल रखा गया कि कोई भी किसान खाली पेट ना सोए।

किसानों की नाराजगी बदल सकती है चुनाव परिणाम

नई दिल्ली | **सुहेल हामिद**

कर्जमाफी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की कुछ मांगों पर सहमति जताकर सरकार ने 'डैमेज कंट्रोल' करने की कोशिश जरूर की, पर आंदोलन सियासी संदेश देने में कामयाब रहा है। अभी तक किसान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान में आंदोलन कर रहे थे। अब हरिद्वार से दिल्ली तक किसान क्रांति यात्रा के जरिए किसानों ने अपनी मांग दिल्ली दरबार तक मजबूती के साथ पहुंचा दी है।

सरकार पर दबाव बनाकर चुनावी साल में किसान अपनी कितनी मांगों को पूरा कराने में सफल रहते हैं, यह वक्त तय करेगा। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत के बाद किसानों का यह पहला बड़ा आंदोलन है। पर इस यात्रा में महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलनों की तरह सभी समुदायों से ताल्लुक रखने वाले किसानों की हिस्सेदारी कम नजर आई। यात्रा में कई प्रदेशों के किसान शामिल हुए, पर जाट किसानों की संख्या अधिक थी।

पुलिस का किसानों के साथ टकराव के बीच सरकार ने जिस तेजी के साथ सुलह-सफाई की कोशिश की है, उससे साफ है कि भाजपा को भी इसके सियासी परिणाम का अंदाजा है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की करीब दो दर्जन सीट हैं।

सियासी गणित

- यात्रा में जाटों की संख्या अधिक बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किल
- पश्चिमी उप्र की दो दर्जन सीट पर है भाजपा का कब्जा

पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पर कैराना उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की तबस्सुम हसन ने भाजपा को शिकस्त दी थी। इस जीत में जाट मतदाताओं की भूमिका अहम रही।

किसान क्रांति यात्रा सियासी तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के लिए सियासी तौर पर ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। पर इसके लिए रालोद को दूसरे विपक्षी दलों के समर्थन की भी जरुरत होगी। यही वजह है कि चौधरी अजित सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने में देर नहीं की। अजित सिंह मानते हैं कि किसान भाजपा के खिलाफ मन बना चुका है। वर्ष 2014 और कैराना चुनाव के बाद सरकार ने कई घोषणा की है। पर कोई पूरी नहीं हुई है। किसान यह समझ चुका है। इसलिए, वह अब भाजपा को वोट नहीं देगा। एनडीए घटकदल के एक बड़े नेता भी मानते हैं कि किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में भाजपा की मुश्किल बढ़ा सकता है। किसान नाराज हैं। खासकर जाट मतदाता काफी सीट पर निर्णायक फैसला करते हैं।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, प्रथम तल, बाबर रोड, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23411411, **फैक्स:** 011-23472550
सीआईएन: L74899DL1998PLC093073
ई-मेल: investors@petronetlng.com, **वेबसाइट:** www.petronetlng.com

सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 60 के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके अधीन प्रस्तुत नियमों के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बेनिफिशयल ओनरशिप की हकदारी पर विचार करने हेतु निम्न विवरणानुसार **रिकार्ड तिथि** तय कर दी गई है:-

ISIN- INE347G08035 यानी रु. 600 करोड़ के 5 वर्ष की अवधि हेतु 9.05% अप्रतिभूत रीडेमेबल करयोग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) (सीरीज़ II) (विकल्प II)।

रिकार्ड तिथि - 13 अक्टूबर, 2018

कथित रिकार्ड तिथि के संबंध में एनएसडीएल एवं सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बेनिफिशल ओनरशिप विवरणों के आधार पर, 28 अक्टूबर, 2017 से 27 अक्टूबर 2018 (दोनों दिवस शामिल) तक की अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान, 29 अक्टूबर, 2018 को किया जाएगा।

कृते पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
हस्ता./-
(राजन कपूर)
उपाध्यक्ष - कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01 अक्टूबर, 2018

कॉरपोरेट की बजाय किसानों का कर्ज माफ करे सरकार

देविंदर शर्मा
कृषि विशेषज्ञ

केंद्र सरकार के लिए दशकों से किसानों के साथ हो रहे अन्याय का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। यह सही मौका है, जब सभी किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनको बचाने के लिए सरकार को कर्जा माफ करना चाहिए। आखिर कॉरपोरेट घरों को भी सरकार कर्जा माफ करती है फिर देश के अन्नदाता का कर्जा माफ करने में हीला हवाली क्यों हो रही है।

एक अनुमान के मुताबिक देश के किसानों पर लगभग 12 लाख 60 हजार करोड़ रुपये कर्ज है, इसे चरणों में माफ किया जा सकता है। किसान को एक लाख कर्ज नहीं अदा करने पर जेल में ठूंस दिया जाता है। वहीं, कॉरपोरेट घराने के किसी व्यक्ति को आज तक जेल नहीं भेजा गया। इसके उलट उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। वर्तमान में 10 लाख 30 हजार रुपये कॉरपोरेट घरानों पर कर्ज नहीं लौटाने के कारण एनपीए हो चुका है।

किसानों को जब उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो वह कर्ज में डूबेंगे ही। पंजाब में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1700 रुपये प्रति कुंतल है जबकि किसानों से 1073 रुपये में खरीद हो रही है। मूंग की एमएसपी 6975 रुपये है, किसानों को 5000 रुपये में बेचनी पड़ रही है। इसी प्रकार सोयाबीन की एमएसपी 3399 रुपये प्रति कुंतल है जबकि खरीद 4600 रुपये प्रति कुंतल हो रही है। किसान की फसल की लागत प्रति बीघा 3000 रुपये आती है जबकि उसको दाम 2000 रुपये प्रति बीमा मिलता है। ऐसे में उसकी आर्थिक रूप से कमर टूट रही है। पुरानी कहावत है कि किसान अपनी उपज होलसेल में बेचता है और फुटकर में खरीदता है। उस पर भाड़ा अपनी जेब से देता है।

सरकार उपज को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा करती है लेकिन उसका दाम किसान को शायद ही मिलता हो। उपज का सही दाम किसानों को दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबल के लिए बिजली मुफ्त देनी चाहिए।

सरकार को फसलो की सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त अथवा सब्सिडी पर बिजली देनी चाहिए। लाभकारी मूल्य व लागत कम करके किसानों की काफी मदद की जा सकती है।

सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना असल में उपज की बीमा नहीं बल्कि निजी इंश्योरेंस कंपनियों का बीमा हुआ है। पिछले आंकड़ों पर नजर डाले तो इंश्योरेंस कंपनियों ने 22 हजार करोड़ रुपये किसानों से प्रीमियम के रूप में वसूले जबकि बीमित फसल के भुगतान में सिर्फ आठ हजार करोड़ रुपये खर्च किए। इस प्रकार एक सीजन में कंपनियों को 14 हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ। किसानों के साथ हो रही इस लूट-खसोट को रोकने के लिए सरकारी बीमा कंपनियों को आगे लाना होगा।

10 साल पुराने ट्रैक्टर को चलाने पर प्रतिबंध दरअसल वाहन निर्माता कंपनियों को फायदा पहुंचाने का फार्मूला है। यह नियम निजी कारों व ट्रकों पर भी लागू होती है। सरकार को उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अविलंब कदम उठानी चाहिए।

प्रस्तुति : अरविंद सिंह